



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2012/वैशाख 4, 1934

No. 94]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2012/VAISAKHA 4, 1934

कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

गुलबर्गा, 30 मार्च, 2012

परिनियम 43

विश्वविद्यालय प्राधिकरण के रूप में स्कूल बोर्ड का सम्मिलन

विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत धारा 19(6) 25 और 26(a)

सं. सीयूके/जीओवी/एफ-1/2011-12/1360/1.—कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् में विद्यापरिषद् के द्वारा प्रस्तावित किया गया प्रस्ताव के आधार पर एक नए परिनियम का निर्माण किया। इसमें स्कूल बोर्ड को विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में सम्मिलित किया गया है। विश्वविद्यालय के मौजूदा परिनियमों में एक नया परिनियम बनाया गया।

प्रस्तावना.— विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम 15(2) के अनुसार प्रत्येक स्कूल के स्कूल बोर्ड हो। संकाय/विद्यापीठ की शिक्षण प्रणाली में अनेक विभाग एक ही विद्यापीठ के अंतर्गत आते हैं। इसके द्वारा उत्तम शैक्षणिक सहकारिता, सहभागिता, अंतरविद्यावर्ती और बहुआयामी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि स्कूल बोर्ड के अधिनियम की धारा 19 के तहत स्कूल बोर्ड विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में सम्मिलित किया जाए। विभाग के बोर्ड ऑफ स्टडीज पहले से परिनियम में सम्मिलित हैं।

अतः परिनियम

सम्मिलित परिनियम 43 (परिनियम 42 के उपरांत)

44-विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में स्कूल बोर्ड को जोड़ा जाए।

परिनियम-44**छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष****अधिनियम की धारा 27(2)**

कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में विद्या-परिषद् द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर विश्वविद्यालय के मौजूदा परिनियमों में जोड़ते हुए छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का एक पद सृजन करने हेतु एक नया परिनियम बनाती है।

प्रस्तावना : जैसा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम का परिनियम 36(1) (i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के संबंध में बताता है, अधिनियम में छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति के माध्यम या प्रक्रिया के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इसकी व्यवस्था करते हुए परिनियम को बनाना आवश्यक है।

इसलिए यह परिनियम है।

परिनियम-44 जोड़ें (परिनियम-43 के उपरांत) : छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष

1. प्रत्येक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से कुलपति की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् द्वारा नामित किया जाएगा, जोकि एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे श्रेणी का नहीं होगा।
2. अनुच्छेद-1 के अंतर्गत नियुक्त प्रत्येक संकायाध्यक्ष एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और 3 वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।
3. परन्तु कार्यपरिषद्, यदि यह विचार करना आवश्यक समझती है तो, कुलपति की अनुशंसा पर एक शिक्षक, जोकि एक एसोसिएट प्रोफेसर के श्रेणी से नीचे नहीं हो, को उसके कर्तव्यों के अलावा, छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों के पालन हेतु नामित कर सकती है और ऐसी प्रकरण में उक्त शिक्षक को कार्यपरिषद् एक उचित भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति दे सकती है।
4. एक व्यक्ति, जोकि छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, का अपने मूल पद पर धारणाधिकार जारी रहेगा और उन सभी लाभों का पात्र होगा जोकि अन्यथा उसे मिलते, यदि उसकी नियुक्ति छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में न होती।
5. जब एक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का कार्यालय रिक्त है अथवा जब छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, किसी बीमारी के कारण अथवा अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य वजह से, उसके कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, कार्यालयीय कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए की जाएगी।
6. छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों और शक्तियों को अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

परिनियम (45)**शास्त्रीय भाषा केंद्र (कन्नड) की स्थापना****परिनियम की धारा 26 (के)**

कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में विद्यापरिषद द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव को एक नया परिनियम के प्रस्ताव को शास्त्रीय भाषा (कन्नड) केंद्र की स्थापना के लिए वर्तमान विश्वविद्यालय के परिनियम में एक और परिनियम बनाया है।

प्रस्तावना— शास्त्रीय भाषा के स्तर के परिणाम के तरह कन्नड पर भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सिफारिश और अनुमोदन के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शास्त्रीय भाषा केंद्र की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों को चिन्हित के लिए संपर्क किया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके लिए स्थापित समिति की सिफारिश के आधार पर कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय को शास्त्रीय भाषा केंद्र की स्थापना के लिए चयनित किया गया।

अतः परिनियम

परिनियम

परिनियम 45 को जोड़ना (परिनियम 44 के उपरांत)

45. शास्त्रीय भाषा केंद्र (कन्नड) की स्थापना हो। इसके आधार पर कर्तव्य एवं शक्तियाँ अध्यादेश के द्वारा निर्धारित की जाए।

उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा उनके पत्रांक एफ.42-26/2009-डैस्क्यू दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के माध्यम से उपरोक्त परिनियम की कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमति की सूचना भेजी गई है।

ह./- अपठनीय

(रजिस्ट्रार)

[विज्ञापन III/4/218-के/12/अस।]

CENTRAL UNIVERSITY OF KARNATAKA

NOTIFICATION

Gulbarga, the 30th March, 2012

STATUTE (43)

INCLUSION OF SCHOOL BOARD AS AUTHORITY OF THE UNIVERSITY

[Under Section 19(6), 25 and 26(a) of the University Act]

No. CUK/GOV/F-1/2011-12/1360/1.—The Executive Council of Central University of Karnataka, on the proposal made by the Academic Council, hereby makes a new Statute providing for the Inclusion of School Board as Authority of the University by way of addition to the existing Statutes of the University.

PREAMBLE: Statute 15(2) of the University Act stipulates that the every School will have School Board. In the Schools of Studies system, several Departments are placed under the same School so as to encourage greater academic cooperation and coordination and promote inter disciplinary and multidisciplinary studies. It is therefore necessary that the School Board should be included as an authority of the University under Section 19 of the Act where the Board of Studies of the Departments is already included.

Hence, the Statute.

Add Statute 43 (after Statute 42)

43 – The School Board shall be included as an Authority of the University.

STATUTE (44)
DEAN OF STUDENTS' WELFARE
(Section 27(2) of the Act)

The Executive Council of Central University of Karnataka, on the proposal made by the Academic Council, hereby makes a new Statute providing for the creation of a post of Dean, Students' Welfare by way of addition to the existing Statutes of the University.

PREAMBLE : While Statute 36 (1) (i) of the Central Universities Act speaks of the Dean of Students' Welfare, there is no provision in the Act for the mode and procedure for appointment of Dean of Students' Welfare. Hence it was felt necessary to frame statute prescribing the same.

Hence the Statute.

Add Statute 44 (after Statute 43): DEAN OF STUDENTS' WELFARE.

1. Every Dean of Students' Welfare shall be appointed from amongst the teachers of the University, not below the rank of a Associate Professor by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor
2. Every Dean appointed under clause (1) shall be a whole-time officer and shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.
3. Provided that the Executive Council may, if it is considered necessary, appoint, on the recommendation of the Vice-Chancellor, a teacher, not below the rank of a Associate Professor, to discharge the duties of the Dean of Students' Welfare in addition to his duties as such teacher and in such a case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him.
4. A person who is appointed as a Dean of Students' Welfare shall continue to hold his lien on his substantive post and shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him, but for his appointment as the Dean of Students' Welfare.

5. When the office of a Dean of Students' Welfare is vacant or when the Dean of Students' Welfare is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
6. The duties and powers of a Dean of Students' Welfare shall be prescribed by the Ordinances.

STATUTE (45)

ESTABLISHMENT OF CENTRE FOR CLASSICAL LANGUAGE (KANNADA)

Section 26(k) of the Act

The Executive Council of Central University of Karnataka, on the proposal made by the Academic Council, hereby makes a new Statute providing for the Establishment of Centre for Classical Language (Kannada) by way of addition to the existing Statutes of the University.

PREAMBLE: Consequent to according the status of classical language on Kannada, the Govt. of India after approval and upon the recommendations of the Ministry of Human Resource Development have communicated to UGC to identify universities for the establishment of Centers in Classical languages.

The UGC, based on the recommendations of a committee constituted for this purpose, has identified the Central University of Karnataka for the establishment of Centre for Classical Language (Kannada).

Hence the Statute.

STATUTE

Add Statute 45 (after Statute 44)

45. "There shall be established a Centre for Classical Language (Kannada). The powers and functions shall be as prescribed by the Ordinances.

The Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, New Delhi vide its letter No. F.42-26/2009-Desk (U) dated 19th April, 2011 has communicated the assent of the Visitor to the above Statute.

Sd./- Illegible
(Registrar)

[ADVT. III/4/218-K/12/Exty.]

1445 90/12-2